

दैनिक

गाजियाबाद से प्रकाशित हिन्दी दैनिक

वेलाकम इंडिया

RNI NO. UPHIN/2018/76874

नये भारत की नई सोच

वर्ष: 07 अंक: 185

मंगलवार, 14 जुलाई-2026 (गाजियाबाद)

पेज-8

मूल्य-एक रुपया

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, ट्रस्ट को जारी किया नोटिस

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर का प्रबंधन करने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी से मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट दखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 20 जुलाई की होगी।

जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुर्वकांत, जस्टिस जांयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पीठ



के समक्ष पेश हुए। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्टेटस रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस टालने की अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मामले से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड को भी संरक्षित करने की

जरूरत थी। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि उन्हें भी जांच की स्टेटस रिपोर्ट मुहैया कराई जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि 'हम इस बारे में बाद में देखेंगे क्योंकि अभी जांच जारी है।'

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने रित याचिका दायर की है। इनके अलावा अजय कुमार राय और अन्य की ओर

से श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट और अन्य के खिलाफ दायर एक क्रिमिनल रिट याचिका और आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की एक अलग याचिका शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से कर दिया था इनकार

इससे पहले, जब जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और शील नागू की पीठ के

मंदिरों के दान को सुरक्षित बनाने के लिए निर्देश देने की मांग

सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की गई थी कि वह राष्ट्रीय महत्व के मंदिरों में जनता से मिलने वाले दान और चढ़ावे को पारदर्शी तरीके से संभालने के लिए कम से कम संवैधानिक सुरक्षा उपाय बनाने का निर्देश दे। इस बीच, सांसद सुधाकर सिंह ने चल रही जांच को सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उनकी याचिका में ट्रस्ट के धर्मनिरपेक्ष वित्तीय मामलों की देखरेख के लिए रिटायर न्यायिक अधिकारियों और वित्तीय विशेषज्ञों की एक अस्थायी, कोर्ट की निगरानी वाली समिति बनाने, सभी वित्तीय रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगाने, व्यापक फॉरेंसिक ऑडिट कराने और ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑडिट किए गए वित्तीय स्टेटमेंट और दान का विवरण प्रकाशित करने की भी मांग की गई है।

सामने गोस्वामी की याचिका का जिफ़र किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ता ने मामले को तुरंत लिस्ट करने पर जोर दिया था और कहा था कि लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं।

मामले की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए न्यायमूर्ति सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिया था कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद शीघ्र अवलत के फिर से खुलने पर इस मामले को सूचीबद्ध किया जाए।

भारी बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 7 की मौत और 97,000 लोग बुरी तरह प्रभावित



वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में नई बाढ़ और बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से भारी तबाही हुई। इससे सड़कें, पुल, स्कूल और दूसरे सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों का संपर्क टूट गया। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एडउ3) के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, लगातार बारिश के कारण कुरुंग कुमे जिले में अचानक बाढ़ आ गई और पावके के सांग, पश्चिम कामेंग और पापुम पारे जिलों में भूस्खलन हुआ। इस बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या सात बनी हुई है और राज्य के सभी 26 जिलों में 97,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा असर कुरुंग कुमे जिले में देखा गया, जहाँ कुमे नदी के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण सोमवार सुबह पारसी-पारलो सर्कल और दामिन सब-डिविजन में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के पानी ने हुरी और दामिन को जोड़ने वाले पुल को बहा दिया, जिससे सब-डिविजन का सड़क संपर्क टूट गया। पारसी-पारलो सर्कल में, बाढ़ का पानी इंसपेक्शन बंगले में घुस गया, जिससे दो रिहायशी मकानों और एक चर्च को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा और पागम गाँव को जोड़ने वाला पुल बह गया। बाढ़ ने इलाके के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक, सेंट थॉमस स्कूल को भी भारी नुकसान पहुंचाया। पूरा कैपस पानी में डूब गया, जिससे क्लासरूम, स्कूल की इमारतें, पढ़ाने का सामान, फर्नीचर, उपकरण और टीचरों के क्वार्टर को नुकसान पहुंचा। स्कूल में पढ़ाई-लिखाई से जुड़ी गतिविधियाँ अगले आदेश तक रोक दी गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि अचानक आई बाढ़ से कुरुंग कुमे में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों को काफी नुकसान पहुंचा है।

कोलकाता एयरपोर्ट पर 136 साल पुरानी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगी रोक

दो नये कानूनों के जरिये सुवेंदु ने दंगाइयों पर शिकंजा और कसा

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। कोलकाता हवाई अड्डे के भीतर स्थित लगभग एक सौ छत्तीस वर्ष पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज के लिए प्रवेश पास पर रोक और राज्य सरकार द्वारा लागू किए गए नये सुरक्षा कानूनों ने पश्चिम बंगाल की राजनीति तथा प्रशासनिक व्यवस्था के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न ला खड़ा किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और हवाई अड्डे की सुरक्षा हर दूसरी प्राथमिकता से ऊपर है।

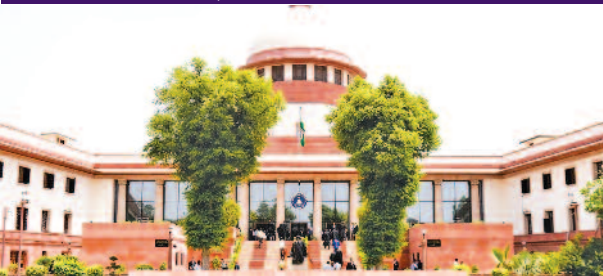
हम आपको बता दें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के भीतर स्थित यह मस्जिद लंबे समय से विवाद का विषय रही है। हवाई अड्डे के दो रनवे हैं, जिनमें दूसरा रनवे अपेक्षाकृत छोटा है और उसी के निकट यह मस्जिद स्थित है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मुख्य रनवे किसी कारण से बंद हो जाए तो दूसरे रनवे का पूरा उपयोग आवश्यक हो जाता है। ऐसे में मस्जिद की मौजूदगी न केवल रनवे विस्तार की योजना में बाधा बन रही है, बल्कि विमान संचालन की दृष्टि से भी जोखिम पैदा



करती है। यही कारण है कि हवाई अड्डा प्रशासन लंबे समय से इसके स्थानांतरण पर विचार करता रहा है। इसी पृष्ठभूमि में हवाई अड्डा प्रशासन ने सामूहिक नमाज के लिए प्रवेश पास जारी करना बंद कर दिया है और परिसर में अतिरिक्त पुलिस तथा सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई है। यह कदम किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भी दोहराया कि किसी को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका गया है। उन्होंने बकरीद और मुहर्रम का उदाहरण देते हुए कहा कि कानून का पालन करते हुए धार्मिक आयोजन शांतिपूर्वक संपन्न हुए और आगे भी धर्म को व्यक्तिगत आस्था तक

सीमित रखते हुए कानून का सम्मान करना ही सभी नागरिकों का दायित्व है।

दमदम उत्तर से विधायक सौरव सिकंदर ने भी सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए फोटो सहित बायोमेट्रिक पास अनिवार्य होता है, जबकि नमाज के लिए आने वाले लोगों के संबंध में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उनका कहना है कि यह मस्जिद अत्यधिक सुरक्षा वाले स्तर तीन क्षेत्र में स्थित है, जहां से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अति विशिष्ट व्यक्तियों के आवाजाही होती है और हर महीने लाखों यात्री गुजरते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढील भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने भी इस निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनका मानना है कि अब सरकार विकास और सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता देते हुए मस्जिद के स्थानांतरण का रास्ता साफ करेगी ताकि रनवे विस्तार का कार्य भी बिना बाधा आगे बढ़ सके।



वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि नागरिकता और विदेशी होने के दर्जे से जुड़े मामलों का फैसला 'निष्पक्ष, कानूनी और उचित' प्रक्रिया के जरिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें असम में 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के आदेश को सही ठहराया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 27 अपीलों को मंजूरी दी और मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण) के पास वापस भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता एक बहुत ही अहम संवैधानिक और कानूनी मामला है, इसलिए सुनवाई के दौरान निष्पक्षता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। लाइव-लॉ ने बेंच के हवाले से कहा कि नागरिकता और विदेशी होने

का दर्जा संवैधानिक और कानूनी तौर पर बहुत अहम है। राज्य को यह जायज और जरूरी जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जो लोग कानूनी तौर पर भारतीय नागरिकता का दाना करने के हकदार नहीं हैं, वे प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल करके, झूठे दावे करके या घरेलू फालतू उठाकर यह दर्जा हासिल न कर सकें। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह मकसद प्रक्रिया से जुड़े सुरक्षा उपायों से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा साथ ही, इस तरह के स्टेटस का फैसला एक ऐसी प्रक्रिया से होना चाहिए जो निष्पक्ष, कानूनी और उचित हो। फॉरेनर्स एक्ट, 1946 की धारा 9 के तहत कानूनी जिम्मेदारी पूरी तरह से लागू रहेगी।' बेंच ने साफ किया कि उसका आदेश सिर्फ मामलों का नए सिरे से और कानूनी रूप से सही फैसला सुनिश्चित करने तक ही सीमित था और उसने अपील करने वालों की नागरिकता के दावों की असलियत की जांच नहीं की थी।

कर्नाटक सरकार ने मंदिरों के चढ़ावे में पारदर्शिता के लिए जारी की नई एसओपी, डिजिटल भुगतान और सीसीटीवी अनिवार्य

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने राज्य द्वारा संचालित मंदिरों में मिलने वाले चढ़ावे की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत मंदिर परिसरों में सीसीटीवी या वेब कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले दान के लिए क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है।

यह कदम अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के कथित मामले के बाद उठाया गया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पिछले हफ्ते ही अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि राज्य के हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (मुजराई) विभाग के सभी बड़े मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के दान-पात्रों से चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह एहतियाती कदम जरूरी हो गए थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मुजराई विभाग के अधीन आने वाले मंदिरों में हंडी यानी दान-पात्र के पैसों और गहनों की गिनती को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। बड़े मंदिरों में हर



इसी को रोकने के लिए अब सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्डिंग फुटेज सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा। इन कैमरों की लगातार निगरानी मुजराई विभाग के मुख्यालय के साथ-साथ उपायुक्त और उपमंडल अधिकारियों के कार्यालयों से की जाएगी। डिजिटल भुगतान की बढ़ावा देने के लिए मंदिरों में क्यूआर कोड लगाए जाएंगे जिसमें बैंक का आईएफएससी कोड और अन्य जरूरी जानकारी भी होगी। इसे मंदिर की लेखा प्रणाली के साथ सीधे जोड़ा जाएगा ताकि वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी रहे। चोरी रोकने के लिए यह भी तय किया गया है कि कैमरों के लेंस को कपूर के धुएँ या अन्य तरीकों से बाधित न किया जा सके इसके लिए विशेष वेब कैमरों का इस्तेमाल होगा और मुजराई विभाग के मुख्यालय में एक केंद्रीय सर्वर स्थापित किया जाएगा। दान की गिनती की प्रक्रिया को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए हैं। बड़े मंदिरों में हर

हफ्ते और अन्य सक्रिय मंदिरों में हर दो हफ्ते में एक बार तहसीलदार की देखरेख में गिनती की जाएगी। गिनती के दौरान राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी और तारीखें आधिकारिक कैलेंडर में पहले से तय की जाएंगी। सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं का भूख्य उसी दिन आंका जाएगा और उन्हें तुरंत जिला या सब-ट्रेजरी में जमा कराया जाएगा। प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए गिनती में शामिल कर्मचारियों के लिए चेहरा मिलान प्रणाली यानी फेस मैचिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। हंडी खोलने से लेकर बैंक की नकदी सौंपने तक की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी जिसमें तारीख और समय का स्पष्ट उल्लेख होगा। खास बात यह है कि गिनती के काम में आम लोगों के बजाय केवल होमगार्ड, बैंक कर्मचारियों या सरकारी कर्मचारियों को ही लगाया जाएगा।

अमरनाथ यात्रा: कड़ी सुरक्षा के बीच 7,754 श्रद्धालुओं का नया जन्म से रवाना

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। कश्मीर घाटी में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा की वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए सोमवार को जम्मू के दो आधार शिविरों से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7,700 से अधिक श्रद्धालुओं का 12वां जत्था रवाना हुआ। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पवित्र गुफा मंदिर में अब तक 2,52,000 से अधिक तीर्थयात्री भगवान शिव के 'हिमालिंगम' के दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार को रवाना हुए कुल 7,754 तीर्थयात्रियों में 5,383 पुरुष, 2,071 महिलाएं, 222 साधु, 58 साध्वियां, 16 बच्चे और चार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। ये सभी श्रद्धालु कुल 303 वाहनों के काफिले में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े। सुरक्षा कारणों से इस काफिले



को दो अलग-अलग समूहों में बांटा गया था। बालटाल मार्ग से जाने वाला पहला काफिला तड़के 3:30 बजे रवाना हुआ, जिसमें 133 गाड़ियों में 2,896 तीर्थयात्री सवार थे। वहीं, पहलगाम मार्ग से जाने वाला दूसरा काफिला सुबह 4:05 बजे निकला, जिसमें 170 वाहनों में 4,858 श्रद्धालु सवार थे। दो जुलाई को यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक कुल 87,701 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से कश्मीर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, जिसमें शुक्रवार को रवाना हुए श्रद्धालु भी शामिल हैं।

वेलकम इंडिया, नेटवर्क

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में कहीं भी बकरीद या किसी अन्य दिन गाय या बछड़े के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटिशन पर नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें पूरे राज्य में गावों और बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का अंतिम पैराग्राफ, जिसमें राज्यभर में प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था, प्रथम दृष्टया सुधार की

मांग करता है। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। राज्य सरकार ने दलील दी कि हाई कोर्ट का आदेश तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम, 1958 के विपरीत है।

इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर 10 वर्ष से अधिक उम्र की उन गायों के वध की अनुमति दी जाती है, जो काम करने और प्रजनन के लिए अनुपयुक्त हो चुकी हों। सरकार ने यह भी कहा कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, पशु क्रूरता निवारण (वध गृह) नियम, 2001, तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय अधिनियम, 1998 तथा तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय नियम, 2023 जैसे अन्य कानून वध की प्रक्रिया और शर्तों को निश्चित करते हैं, लेकिन इनमें



कहीं भी पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान नहीं है। राज्य का कहना है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाकर हाई कोर्ट ने वैधानिक कानून की जगह न्यायिक कानून बना दिया। मद्रास हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण शामिल थे, ने 27 मई को बकरीद से ठीक पहले यह आदेश पारित किया था। यह

दिया। आदेश पारित करते समय हाई कोर्ट ने एक सरकारी आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए गो वध पर प्रतिबंध आवश्यक है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उन पुराने फैसलों का भी उल्लेख किया, जिनमें कहा गया था कि बकरीद के अवसर पर गो वध इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

राज्य सरकार ने कहा कि जब मौजूदा कानून निर्धारित स्थानों पर गायों की एक विशेष श्रेणी के वध की अनुमति देता है, तब उसके विपरीत कोई न्यायिक निर्देश नहीं दिया जा सकता। सरकार ने यह भी आपर्ति जताई कि हाई कोर्ट ने सरकारी आदेश संख्या 1715 पर बरोसा किया, जबकि उसकी वैधता या लागू होने का सवाल

था। आदेश के सामने कभी उठा ही नहीं आया। सरकार का कहना है कि कोई भी कार्यकारी आदेश राज्य में लागू कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता।

व्या हाई कोर्ट ने याचिका के दायरे से बाहर जाकर फैसला दिया?

स्पेशल लीव पिटिशन में राज्य सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका केवल कोयंबटूर में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर गायों के वध को रोकने तक सीमित थी। इसके बावजूद डिवीजन बेंच ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए पूरे राज्य में गायों के वध पर हर परिस्थिति में प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि अधिकृत बूचड़खानों में भी, जबकि याचिकाकर्ता ने ऐसी कोई राहत नहीं मांगी थी।

संपादक की कलम से

युद्धविराम का मिथक और वैश्विक शांति का संकट

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच समय-समय पर घोषित होने वाले युद्धविराम और शांति प्रयासों ने विश्व समुदाय के सामने अनेक गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जब जब युद्धविराम की घोषणा हुई, कुछ ही समय बाद नए हमले, नई सैन्य



ललित शर्मा

संपादक

सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है, जबकि आलोचकों का मानना है कि अमेरिका के दोहरे मानदंड उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। दूसरी ओर इजरायल का कहना है कि उसकी सैन्य कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है, जबकि उसके विरोधियों का आरोप है कि अत्यधिक सैन्य बल से क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है। ईरान स्वयं को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता रहा है। अनेक पश्चिमी देश और कुछ क्षेत्रीय सरकारें आरोप लगाती रही हैं कि ईरान कुछ सशस्त्र संगठनों को समर्थन देता है, जबकि ईरान इन आरोपों से इनकार करता है और अपनी नीति को राष्ट्रीय सुरक्षा तथा क्षेत्रीय संतुलन का हिस्सा बताता है। यही परस्पर अविश्वास इस संघर्ष को और गहरा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनेक अवसरों पर कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईरान वांता के लिए आगे आता है तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। इन दो संदेशों कड़े सैन्य रुख और कूटनीतिक संवाद के बीच का विरोधाभास विश्व समुदाय को असमंजस में डालता है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेजामिन नेतन्याहू लगातार यह कहते रहे हैं कि इजरायल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर हर खतरे का जवाब देगा। इसके अनुसार ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताएँ इजरायल के अस्तित्व के लिए चुनौती हैं। दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और ईरानी नेतृत्व बार-बार यह कहते रहे थे कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और अपनी संप्रभुता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करेगा। ईरान यह भी आरोप लगाता है कि अमेरिका और इजरायल क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देते हैं। इन परस्पर विरोधी बयानों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि सभी पक्ष स्वयं को शांति का समर्थक बताते हैं, तो युद्ध की आग बार-बार क्यों भड़क उठती है? क्या युद्धविराम वास्तव में स्थायी शांति का माध्यम है, या केवल सैन्य और कूटनीतिक पुनर्संयोजन का अवसर? संयुक्त राष्ट्र महासचिव पंतोनियो गुटेरेस ने कई बार सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और तत्काल तनाव कम करने की अपील की है। उनका स्पष्ट मत रहा है कि मध्य-पूर्व किसी और युद्ध का भार नहीं उठा सकता। यह कथन केवल एक क्षेत्र की चिंता नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य की चेतावनी है।

वक्त की कीमत

उदय किशोर साह

कविता



जिसने भी वक्त की कीमत पहचाना

बन गया वो सिकन्दर का भी नाना

हौसले को मत दो जीवन में विश्राम
दिन ढ़ल जाये या हो जाने दो शाम

जीवन चलने का नाम है मेरे भाई

आगे बढ़ना निरंतर जीवन में साईं
असफलता के आगे तेरी है मुकाम
दिन ढ़ल जाये या हो जाने दो शाम

नदिया सागर से मिलने दौड़ लगाई

पथरों चट्टानों से भी वो टकराई

कदम उनकी कब रुका कब ली विराम

दिन ढ़ल जाये या हो जाने दो । शाम

पवन पुरवाई सागर से बहकर आई

पर्वत जंगल उनकी राह ना रोक पाई

मजिल पहुँच कर ती है आज विश्राम

दिन ढ़ल जाये या हो जाने दो । शाम

जग में कोई काम कठिन ना है । भाई

मिहनत के आगे हर अड़चन शीश झुकाई

लगन तुम्हारी कोई कर ना पाये नाकाम

दिन ढ़ल जाये या हो जाने दो । शाम

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक ललित कुमार द्वारा वेलकम इंडिया प्रिन्टर्स, 1/26, साउथ साइड, जी टी रोड, गाजियाबाद -201001 से मुद्रित करारक ग्राउन्ड फ्लोर, दुर्गा टॉवर, आर.डी. सी राजनगर, गाजियाबाद 201002 से प्रकाशित किया | संपादक : ललित शर्मा

सम्पर्क सूत्र: 9891116568

किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा गाजियाबाद न्यायालय में ही होगा ।

प्रकृति नहीं, मनुष्य का विवेकहीन अहंकार ही

महाविनाश का कारण



एन0के0शर्मा

लेखक

मानव सभ्यता आज अपने इतिहास के ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी है जहाँ विकास, विज्ञान और तकनीकी उपलब्धियों पर गर्व करने वाला मनुष्य स्वयं अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का निमाता बन चुका है। विडंबना यह है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है—भीषण बाढ़, भूकंप, जंगलों की आग, सूखा, चक्रवात, भूस्खलन या ग्लेशियरों का टूटना—तो दोष सीधे प्रकृति पर मढ़ दिया जाता है। समाचारों में अक्सर कहा जाता है कि 'प्रकृति का क्रहर', 'प्रकृति का प्रकोप' या 'प्राकृतिक आपदा'। किंतु यदि घटनाओं की तह तक पहुँचा जाए तो स्पष्ट होता है कि अधिकांश विनाशकारी परिस्थितियों की वास्तविक जड़ प्रकृति नहीं, बल्कि मनुष्य का विवेकहीन अहंकार, असीमित लालच और प्रकृति के नियमों की अवहेलना है।

प्रकृति कभी विनाश की पक्षधर नहीं रही। वह सृष्टि की जननी है, संतुलन की संरक्षिका है और जीवन की आधारशिला है। प्रकृति का प्रत्येक नियम संतुलन, सह अस्तित्व और निरंतरता पर आधारित है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश—इन पंचमहाभूतों के संतुलन ने करोड़ों वर्षों से जीवन को संभव बनाया है। किंतु आधुनिक मनुष्य ने स्वयं को प्रकृति का अंग मानने के बजाय उसका स्वामी समझ लिया। यही विचार मानव सभ्यता की सबसे बड़ी वैचारिक भूल सिद्ध हो रही है।

औद्योगिक क्रांति के बाद विकास



की परिभाषा बदल गई। जंगलों को संसाधन माना गया, नदियों को उद्योगों और समुद्रों को व्यापारिक मार्ग। विकास की अंधी दौड़ में यह भूल गया कि जिन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जा रहा है, वे केवल आर्थिक संपत्ति नहीं, बल्कि जीवन के मूलाधार हैं। परिणामस्वरूप पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर ऊपर उठ रहा है, जैव विविधता नष्ट हो रही है और मौसम का स्वाभाविक चक्र असंतुलित होता जा रहा है।

आज विश्व के अनेक महानगर प्रदूषण के घने आवरण में घुट रहे हैं। शुद्ध वायु विलासिता बनती जा रही है। नदियाँ, जिन्हें भारतीय संस्कृति में माता का स्थान प्राप्त है, औद्योगिक अपशिष्ट और रासायनिक प्रदूषण से कराह रही हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन धरती की कोख को खोखला कर रहा है। कृषि भूमि रसायनों से विषाक्त हो रही है। समुद्र प्लास्टिक कचरे से भरते जा रहे हैं। इन सबके बावजूद मनुष्य स्वयं को विकसित और सभ्य कहने का दावा करता है। विडंबना यह है कि मानव ने

विज्ञान को साधन के बजाय सत्ता का माध्यम बना लिया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परमाणु शक्ति, जैव-प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और डिजिटल क्रांति जैसी उपलब्धियों मानव कल्याण के लिए थीं, किंतु प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व और लाभ की मानसिकता ने इन्हें भी विनाशकारी दिशा में मोड़ दिया। हथियारों की होड़, जैविक अनुसंधानों का सैन्यीकरण, साइबर युद्ध, परमाणु अस्त्रों का विस्तार और प्राकृतिक संसाधनों पर वैश्विक नियंत्रण की होड़ इस विवेकहीन अहंकार की ही अभिव्यक्तियाँ हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में अंधाधुंध सड़क निर्माण, सुरंगों की अनियोजित खुदाई, अवैज्ञानिक निर्माण कार्य और वनों की कटाई ने भूस्खलनों की आवृत्ति बढ़ा दी है। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को बाँधों, अतिक्रमणों और अवैध खनन से बाधित किया गया। परिणामस्वरूप थोड़ी-सी वर्षा भी भीषण बाढ़ का रूप लेने लगी है। दूसरी ओर वर्षा के अभाव में वही क्षेत्र गंभीर जल संकट का सामना करते हैं। यह प्रकृति का क्रोध नहीं, बल्कि मनुष्य द्वारा प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने का प्रतिफल है। जलवायु परिवर्तन आज केवल

पृथिव्याः'—यह उद्घोष केवल आध्यात्मिक विचार नहीं, बल्कि पर्यावरणीय दर्शन का शाश्वत सूत्र है। भारतीय संस्कृति ने वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पशु-पक्षियों और संपूर्ण जैव जगत को परिवार का अंग माना। आधुनिक सभ्यता ने इसी संबंध को उपभोग और स्वार्थ में बदल दिया।

सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर समाप्त कर दिया है। विलासिता अब आवश्यकता बन चुकी है। उपभोक्तावाद ने संतोष का स्थान ले लिया है। अधिक उत्पादन, अधिक उपभोग और अधिक लाभ की अंधी दौड़ ने पृथ्वी के सीमित संसाधनों पर असहनीय दबाव डाल दिया है। यदि पृथ्वी के सभी संसाधनों का उपभोग विकसित देशों की वर्तमान जीवनशैली के अनुरूप किया जाए, तो एक नहीं बल्कि कई पृथिव्यों की आवश्यकता होगी। यह तथ्य स्वयं आधुनिक विकास मॉडल की सीमाओं को उभारता है।

प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग, सतत विकास, हरित ऊर्जा, जल संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, वृक्षारोपण, कार्बन उत्सर्जन में कमी और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व अब विकल्प नहीं, बल्कि अस्तित्व की अनिवार्यता हैं। किंतु केवल नीतियाँ पर्याप्त नहीं होंगी। सबसे बड़ा परिवर्तन मानव चेतना में आना चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं को प्रकृति का स्वामी मानता रहेगा, तब तक विनाश की प्रक्रिया रुकना कठिन है।

शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरणीय नैतिकता को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर जीवन-मूल्य बनाया जाना चाहिए। शासन-प्रशासन को अल्पकालिक आर्थिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक परिस्थितीय संतुलन को प्राथमिकता देनी होगी। उद्योगों को उत्तरदायी उत्पादन प्रणाली अपनानी होगी। नागरिकों को भी अपने दैनिक जीवन में जल, ऊर्जा और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का संकल्प लेना होगा। यह संघर्ष केवल सरकारों का

नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

यह भी समझना होगा कि प्रकृति प्रतिशोध नहीं लेती, वह केवल संतुलन स्थापित करती है। जब नदियों का मार्ग रोका जाता है तो वे अपना मार्ग स्वयं बनाती हैं। जब जंगल काटे जाते हैं तो वर्षा चक्र बदलता है। जब वातावरण में विषैली गैसें भरी जाती हैं तो जलवायु असंतुलित होती है। जब पृथ्वी को कोख से असीमित खनन किया जाता है तो भूगर्भीय अस्थिरता बढ़ती है। इन घटनाओं को यदि मनुष्य प्रकृति का क्रोध कहता है तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रहा है।

वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है; वास्तविक प्रश्न यह है कि मनुष्य कितना विवेकशील है। विज्ञान, तकनीक और आर्थिक विकास तभी सार्थक हैं जब वे मानव और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित करें। अन्यथा वही प्रगति महाविनाश का कारण बन जाती है।

आज आवश्यकता किसी नए ग्रह की खोज से अधिक, पृथ्वी के प्रति नए दृष्टिकोण की है। आवश्यकता विकास की गति कम करने की नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलने की है। आवश्यकता प्रकृति को जीतने की नहीं, उसके साथ चलने की है। यही सच्चा सतत विकास है, यही सभ्यता का भविष्य है और यही मानवता का वास्तविक उत्थान है।

यदि मानव जाति ने अभी भी अपने विवेक को जागृत नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें वैज्ञानिक प्रगति के लिए नहीं, बल्कि पृथ्वी की सबसे समृद्ध सभ्यता होकर भी अपनी ही जीवनदायिनी प्रकृति को नष्ट कर देने वाले अहंकारी समाज के रूप में याद करेंगी। इसलिए समय का सबसे बड़ा संदेश यही है—महाविनाश का कारण प्रकृति नहीं, बल्कि मनुष्य का विवेकहीन अहंकार है; और यदि इस अहंकार का परिणाम नहीं किया गया, तो इतिहास का अगला अध्याय मानव सभ्यता के पतन का अध्याय होगा।

पुरस्कारों का अर्थशास्त्र



एक साहित्यिक संस्था ने कविता, कहानी, व्यंग्य सहित सात विधाओं में कुल 21 पुरस्कारों की घोषणा की। प्रत्येक विधा में प्रथम पुरस्कार 5,100, द्वितीय 3,100 तथा तृतीय 2,100 निर्धारित किया गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 500 आवेदन शुल्क रखा गया और शर्त यह थी कि प्रतिभागी अपनी पिछले वर्ष प्रकाशित पुस्तक की दो प्रतियाँ आवेदन के साथ भेजें। आकर्षक घोषणा के बाद देशभर से 650 साहित्यकारों ने आवेदन किया, जिससे संस्था को आवेदन शुल्क के रूप में 3,25,000 प्राप्त हुए। निर्धारित तिथि पर वातानुकूलित सभागार में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुल 72,100 की पुरस्कार राशि वितरित की गई तथा आयोजन पर लगभग 32,500 खर्च किए गए। इस प्रकार कुल व्यय 1,04,600 रहा, जबकि 2,20,400 की राशि शेष बच गई। अगले ही दिन संस्था के अध्यक्ष और सचिव को 1,300 पुस्तकें दान करने के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया और तीसरे दिन दोनों अपनी-अपनी पत्नियों के साथ विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। यह प्रसंग एक गंभीर प्रश्न छोड़ जाता है—क्या साहित्यिक पुरस्कारों का उद्देश्य प्रतिभा का सम्मान है, या कहीं वे आवेदन शुल्क आधारित आर्थिक मॉडल में बदलते जा रहे हैं? पारदर्शिता और जवाबदेही ही इस प्रश्न का सबसे विश्वसनीय उत्तर हो सकती है।

आय बढ़ाने का माध्यम? कुछ संस्थाएँ पुरस्कारों के लिए ऐसी शर्तें रखती हैं कि केवल प्रकाशित पुस्तक वाले लेखक ही आवेदन कर सकें। इसके साथ ही पुस्तक की दो या तीन प्रतियाँ भेजना अनिवार्य होता है। आवेदन शुल्क अलग से लिया जाता है।

यदि सैकड़ों लेखक आवेदन करते हैं तो संस्था के पास लाखों रुपये एकत्र हो जाते हैं। पुरस्कारों की संख्या सीमित होती है और अधिकांश प्रतिभागियों को केवल धन्यवाद या सहभागिता प्रमाणपत्र मिलता है। आर्थिक दृष्टि से यह मॉडल संस्थाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होता है, जबकि लेखक अपनी रचना, पुस्तक, डाक व्यय और आवेदन शुल्क सहित पर्याप्त धन खर्च कर देता है।

यहाँ समस्या केवल शुल्क लेने की नहीं है। यदि कोई संस्था पारदर्शी ढंग से बताती है कि आवेदन शुल्क कितना, डाक, निर्णायकों के मानदेय, सभागार, स्मारिका और

प्रशासनिक खर्चों के लिए आवश्यक है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। समस्या यह उत्पन्न होती है जब आय और व्यय का कोई सार्वजनिक विवरण उपलब्ध नहीं होता। लेखकों को यह तक ज्ञात नहीं होता कि निर्णायक कौन हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है और चयन के मानदंड क्या हैं। पारदर्शिता के अभाव में संदेह जन्म लेता है और सम्मान की गरिमा कम होने लगती है।

आज साहित्य में एक नई प्रवृत्ति यह भी देखने को मिल रही है कि पुरस्कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, किंतु उनकी विश्वसनीयता घटती जा रही है। अनेक पुरस्कार ऐसे हैं जिनका साहित्यिक योगदान से अधिक संबंध प्रचार-प्रसार से दिखाई देता है। सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े पोस्टर, भव्य मंच, आकर्षक बैनर और लंबी सम्मान सूची देखने को मिलती है, लेकिन साहित्यिक गुणवत्ता पर गंभीर चर्चा कम दिखाई देती है। सम्मान समारोह कभी-कभी साहित्यिक आयोजन कम और प्रचार

कार्यक्रम अधिक लगने लगते हैं।

इस प्रवृत्ति का सबसे अधिक नुकसान नवोदित लेखकों को होता है। वे सम्मान प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा में आवेदन शुल्क जमा करते हैं, पुस्तकें भेजते हैं और पुरस्कार की आशा करते हैं। कई बार उन्हें केवल सहभागिता प्रमाणपत्र या मंच पर एक तस्वीर मिलती है। धीरे-धीरे यह धारणा बनती है कि साहित्य में भी सफलता का रास्ता गुणवत्ता से अधिक आर्थिक योगदान और संपर्कों से होकर गुजरता है। यह धारणा साहित्य के भविष्य के लिए अत्यंत घातक है।

पुरस्कारों की विश्वसनीयता का दूसरा आधार निर्णायक मंडल होता है। यदि निर्णायक स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिष्ठित हों तथा उनकी चयन प्रक्रिया सार्वजनिक हो, तो पुरस्कार की प्रतिष्ठा स्वतः बढ़ जाती है। किंतु यदि निर्णायकों के नाम गोपनीय रखे जाएँ, चयन के कारण न बताए जाएँ और परिणाम केवल औपचारिक घोषणा बनकर रह जाएँ, तो प्रश्न

उठना स्वाभाविक है। साहित्य में विश्वास ही सबसे बड़ी पूँजी है, और पारदर्शिता उसके संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम है।

यह भी सच है कि सभी साहित्यिक संस्थाओं को एक ही दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। देश में अनेक प्रतिष्ठित संस्थाएँ और अकादमियाँ वर्षों से निष्पक्ष और सम्मानजनक पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। वहाँ आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता या यदि लिया जाता है तो उसका स्पष्ट औचित्य और लेखा-जोखा उपलब्ध रहता है। चयन प्रक्रिया बहुस्तरीय होती है और निर्णायक मंडल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। ऐसे पुरस्कार साहित्यकारों के लिए प्रेरणा बनते हैं और समाज में साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं।

दूसरी ओर कुछ संस्थाएँ पुरस्कारों को नियमित आय के स्रोत के रूप में विकसित करती दिखाई देती हैं। यदि किसी प्रतियोगिता में पाँच सौ या एक हजार आवेदन आते हैं और प्रत्येक के पास बड़ी राशि एकत्र हो जाती है। यदि उसी राशि का बहुत छोटा भाग पुरस्कारों और आयोजन पर खर्च हो तथा शेष राशि के उपयोग का कोई सार्वजनिक विवरण न हो, तो आलोचना होना स्वाभाविक है। साहित्यिक संस्थाएँ सामाजिक विश्वास पर चलती हैं; इसलिए उन्हें आर्थिक पारदर्शिता का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए।

पुरस्कारों के अर्थशास्त्र का एक मनोवैज्ञानिक पक्ष भी है। सम्मान पाने की इच्छा प्रत्येक रचनाकार में होती है। यह स्वाभाविक भी है। किंतु इसी इच्छा का यदि व्यावसायिक दोहन होने लगे तो यह साहित्यिक नैतिकता के विरुद्ध है। सम्मान की खरीद नहीं जा सकता और न ही आवेदन शुल्क के अनुपात में उसका मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। वास्तविक पुरस्कार वह है जिसे समाज और समय स्वीकार करे।

समाधान क्या हो सकता है? सबसे पहले प्रत्येक साहित्यिक संस्था को अपनी आय और व्यय का वार्षिक विवरण सार्वजनिक करना चाहिए। आवेदन शुल्क का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। चयन प्रक्रिया, निर्णायक मंडल, मूल्यांकन के मानदंड और परिणामों की संपूर्ण रिपोर्ट और औपचारिक केवल औपचारिक पुरस्कार वास्तव में साहित्य सेवा के

लिए हैं तो संस्था को यह भी बताना चाहिए कि प्राप्त राशि का कितना भाग साहित्यिक गतिविधियों, पुस्तकालयों, युवा लेखकों, शोध और प्रकाशन पर व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने के बजाय उनकी गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिए। कम पुरस्कार, लेकिन निष्पक्ष चयन और सम्मानजनक राशि, साहित्यकारों के लिए अधिक प्रेरणादायक होगी। पुरस्कार समारोह की भव्यता से अधिक महत्त्व चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता का होना चाहिए। मंच की चमक कुछ घंटों की होती है, किंतु निष्पक्ष सम्मान की प्रतिष्ठा वर्षों तक बनी रहती है।

लेखकों की भी आत्ममंथन करना होगा। केवल सम्मान प्राप्त करने की लालसा में प्रत्येक प्रतियोगिता में आवेदन करना उचित नहीं है। किसी संस्था की विश्वसनीयता, पूर्व इतिहास, चयन प्रक्रिया और पारदर्शिता की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सहभागिता करनी चाहिए। साहित्य का वास्तविक मूल्य पुरस्कारों की संख्या से नहीं, बल्कि रचनाओं की गुणवत्ता और पाठकों के विश्वास से तय होता है।

अंततः साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार समय देता है। अनेक महान साहित्यकार अपने जीवनकाल में उपेक्षित रहे, किंतु उनकी रचनाएँ आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रही हैं। वहाँ अनेक तात्कालिक पुरस्कार समय की धूल में खो गए। इसलिए पुरस्कारों का उद्देश्य साहित्य की सेवा होना चाहिए, न कि साहित्य के नाम पर अर्थसंघर्ष।

साहित्य समाज का नैतिक विवेक है। यदि उसके सम्मान भी आर्थिक अपारदर्शिता और व्यावसायिक मानसिकता के शिकार हो जाएँ, तो यह केवल लेखकों का नहीं, पूरे समाज का नुकसान है। आवश्यकता इस बात की है कि साहित्यिक संस्थाएँ अपने कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्व अपनाएँ तथा लेखक भी सम्मान से अधिक सुजन की गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। पुरस्कार तभी सार्थक हैं जब वे प्रतिभा को प्रोत्साहित, साहित्य को समृद्ध करें और समाज में विश्वास जगाएँ। अन्यथा वे केवल 'पुरस्कारों का अर्थशास्त्र' बनकर रह जाएँगे, जहाँ सम्मान पीछे छूट जाता है और कारोबार आगे निकल जाता है।

विश्व जनसंख्या दिवस 2026 पर सिम्स में व्यापक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सामुदायिक चिकित्सा विभाग के द्वारा परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य एवं युवा सशक्तिकरण पर जनजागरूकता अभियान आयोजित

वेलकम इंडिया ब्यूरो

हापुड़। हापुड़ जनपद के पिलखुवा के स्थित अनवरपुर गांव में विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SIMS), हापुड़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के द्वारा जनसंख्या दिवस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण, परिवार नियोजन, प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा जिम्मेदार अभिभावकत्व के प्रति आमजन को जागरूक करना था। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने तथा सभी नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं समाज अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर उल्लेख करता है। इस वर्ष की वैश्विक थीम 'आज और भविष्य के लिए युवाओं की आशाओं एवं

आकांक्षाओं को साकार करना' रही, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ, सुरक्षित एवं जिम्मेदार जीवन के लिए सही जानकारी एवं अवसर उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सकों, संकाय सदस्यों तथा एमबीबीएस 2023 बैच के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ओपीडी परिसर को जनस्वास्थ्य शिक्षा के एक सशक्त मंच के रूप में विकसित किया गया, जहाँ स्वास्थ्य जागरूकता व्याख्यान, शैक्षणिक पोस्टर प्रदर्शनी, परामर्श सत्र तथा संवादात्मक चर्चाओं के माध्यम से परिवार नियोजन, जन्म अंतराल, प्रजनन स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, जिम्मेदार अभिभावकत्व तथा सरकार के द्वारा संचालित परिवार कल्याण योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। यह कार्यक्रम डॉ. (ब्रिगेडियर) विनीत रस्तोगी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सामुदायिक चिकित्सा विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उनके साथ डॉ.



वंदना कश्यप, सहायक प्रोफेसर तथा डॉ. अरशद हुसैन, सीनियर रजिस्ट्रेंट ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया। उन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित स्वास्थ्य शिक्षा एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए कार्यक्रम को प्रभावी बनाया। कार्यक्रम की विशेष उपलब्धि एमबीबीएस 2023 बैच के विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता रही। विद्यार्थियों ने आकर्षक पोस्टर प्रस्तुतियों, व्यक्तिगत स्वास्थ्य परामर्श, जागरूकता संवाद तथा शैक्षणिक गतिविधियों के माध्यम

से मरीजों एवं उनके परिजनों को परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा जिम्मेदार पारिवारिक जीवन के महत्व से अवगत कराया।

यह सहभागिता सिम्स की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को उत्कृष्ट चिकित्सकीय शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सेवा की भावना से भी विकसित किया जाता है। जागरूकता सत्रों में स्वैच्छिक एवं सूचित परिवार

नियोजन, सुरक्षित मातृत्व, उचित जन्म अंतराल, किशोर स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, बाल टीकाकरण, पोषण, प्रजनन अधिकार तथा समय पर स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व पर विशेष बल दिया गया। साथ ही प्रतिभागियों को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं सरकारी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जे. रामचन्द्रन ने विश्व जनसंख्या

दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं तथा जागरूक एवं जिम्मेदार प्रजनन संबंधी निर्णय ही सतत राष्ट्रीय विकास की आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को सही जानकारी एवं अवसर प्रदान कर ही स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज तथा विकसित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स की उपाध्यक्ष श्रीमती रम्या रामचन्द्रन ने भी सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संस्थान निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास एवं सामुदायिक कल्याण के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जनजागरूकता कार्यक्रम समाज में जिम्मेदार नागरिकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा स्वस्थ एवं जागरूक समाज की नींव मजबूत करते हैं। यह कार्यक्रम डॉ. बरखा गुप्ता, प्राचार्य; डॉ. मेजर जनरल सी. एस. आहलुवालिया, चिकित्सा अधीक्षक; ब्रिगेडियर डॉ. आर. के. सहगल, वरिष्ठ सलाहकार; रेवपुर दत्त,

निदेशक; तथा एन. वर्धराजन, महाप्रबंधक के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। उनके नेतृत्व में संस्थान चिकित्सा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। कार्यक्रम को मरीजों एवं उनके परिजनों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। प्रतिभागियों ने स्वास्थ्य शिक्षा गतिविधियों की सराहना करते हुए कहा कि इस पहल से उन्हें परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभावी उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। संकाय सदस्यों ने कहा कि समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम बेहतर जनस्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। जागरूक नागरिक ही अपने एवं अपने परिवार के स्वास्थ्य से जुड़े जिम्मेदार निर्णय लेकर स्वस्थ समाज एवं संतुलित जनसंख्या विकास में महत्वपूर्ण

योगदान दे सकते हैं। क्षेत्र के अग्रणी चिकित्सा संस्थानों में से एक सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (सिम्स), हापुड़ निवारक स्वास्थ्य सेवाओं, जनस्वास्थ्य शिक्षा, सामुदायिक जागरूकता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निरंतर आगे बढ़ाते हुए नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविरों, जनजागरूकता अभियानों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का आयोजन करता रहेगा। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर सिम्स ने स्वस्थ परिवार, जिम्मेदार अभिभावकत्व, युवा सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, जागरूक प्रजनन निर्णय तथा सतत विकास के राष्ट्रीय एवं वैश्विक प्रयासों में अपनी सक्रिय भागीदारी एवं प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया। आइए, हम सभी मिलकर युवाओं को सशक्त बनाएं, परिवारों को सुदृढ़ करें, जागरूक निर्णयों को बढ़ावा दें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ, समृद्ध एवं सतत भविष्य का निर्माण करें।

युवा उम्र में भी बढ़ रहा है हार्ट अटैक का खतरा समय रहते सतर्क रहना है जरूरी

वेलकम इंडिया ब्यूरो

हापुड़। हापुड़ जनपद में पहले हार्ट अटैक को बढ़ती उम्र की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज 30 से 40 साल की उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलती जीवनशैली, तनाव, गलत खानपान, धूम्रपान, वेपिंग, शारीरिक गतिविधि की कमी और पर्याप्त नींद न लेना इसके प्रमुख कारण बन रहे हैं।



समय रहते इन कारणों को समझकर और सही कदम उठाकर दिल की बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नोएडा के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉ. सुनील सोफत ने बताया ये बताया, 'आज पहले की तुलना में कम उम्र के मरीजों में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी बदलती जीवनशैली है।

वेपिंग, जंक और प्रोसेस्ड फूड का अधिक सेवन, लंबे समय तक बैठे रहना, लगातार तनाव और नींद की कमी दिल की सेहत पर बुरा असर डालते हैं। कई युवा यह मानकर चलते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं हो सकता, इसलिए शुरूआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं।

कम उम्र में हार्ट अटैक हमेशा तेज सीने के दर्द के रूप में नहीं होता। कई बार यह लगातार गैस या सीने में जलन जैसा महसूस हो सकता है। इसके

अलावा अचानक बहुत ज्यादा थकान होना, थोड़ी मेहनत में सांस फूलना, सामान्य व्यायाम न कर पाना या जबड़े, गर्दन और ऊपरी पीठ में बिना कारण दर्द होना भी हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं।

ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से जांच करानी चाहिए। डॉ. सुनील ने आगे बताया '25 वर्ष की उम्र के बाद हर व्यक्ति को समय-समय पर ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए।

रोजाना कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें, लंबे समय तक लगातार बैठने से बचें, धूम्रपान और वेपिंग छोड़ें, संतुलित आहार लें और तनाव को नियंत्रित रखें। उनका कहना है कि आधुनिक इलाज से हार्ट अटैक का सफल उपचार संभव है, लेकिन बचाव ही सबसे बेहतर उपाय है। सही जीवनशैली अपनाकर और नियमित स्वास्थ्य जांच कराकर युवा भी अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।

बछलौता फ्लाईओवर पर दर्दनाक हादसा: बाइक ड्रिवाइजर से टकराई, पिता-पुत्री की मौत, तीन घायल



वेलकम इंडिया ब्यूरो

हापुड़। वेलकम इंडिया राजेंद्र सिंह वरिष्ठ जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ क्षेत्र में दोपहर करीब 3:30 बजे बछलौता फ्लाईओवर पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक मासूम बच्ची और उसके पिता की मौत हो गई, जबकि परिवार के तीन अन्य सदस्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार, शाहजहांपुर जनपद के थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम हसनपुर निवासी अशोक (पुत्र रामेश्वर दयाल) अपनी पत्नी रंजिती (42 वर्ष), पुत्र अनुज (14 वर्ष), पुत्री मीनाक्षी (8 वर्ष) और पुत्री राधिका (4 वर्ष) के साथ मोटरसाइकिल (संख्या व्द 16 एड 6339) से नोएडा काम के लिए जा रहे थे।

बछलौता फ्लाईओवर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर ड्रिवाइजर से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि चार वर्षीय राधिका की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही थाना बाबूगढ़ प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। सभी घायलों को एंबुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवाया गया, जहां उपचार के दौरान अशोक की भी मृत्यु हो गई। घटना में घायल रंजिती, अनुज और मीनाक्षी का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है तथा शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुदाफरा चौकी में तैनात राहुल चौहान बने हेड कांस्टेबल,थानाध्यक्ष ने लगाई फीत

वेलकम इंडिया ब्यूरो

हापुड़। हापुड़ जनपद के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस विभाग के लिए एक हॉपेल्लास का समाचार सामने आया है। क्षेत्र की मुदाफरा पुलिस चौकी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे कांस्टेबल राहुल चौहान की पदोन्नति (प्रमोशन) हो गई है। वे अब कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर थाने और चौकी परिसर में खुशी का माहौल है। अधिकारियों ने दी बधाई और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं। पदोन्नति के बाद बाबूगढ़ थाना परिसर में एक सादे और गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाबूगढ़ थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) नवीन गौतम ने संयुक्त रूप से राहुल चौहान के कंधों पर हेड कांस्टेबल की फीत (स्टार/बैज) लगाई। अधिकारियों ने



उन्हें मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। 2015 के बैच के है राहुल चौहान बाबूगढ़ थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने इस मौके पर कहा कि पदोन्नति केवल एक पद का बढ़ना नहीं है, बल्कि यह अपने साथ और अधिक जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मांग करती है। उन्हें पूरा विश्वास है कि राहुल चौहान आगे

भी इसी तरह जनता की सेवा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। सहकर्मियों ने बताया हर्ष राहुल चौहान की इस पदोन्नति पर मुदाफरा चौकी और बाबूगढ़ थाने के समस्त पुलिस स्टाफ ने उन्हें बधाई दी। सहकर्मियों का कहना है कि राहुल चौहान हमेशा से अपने काम के प्रति गंभीर रहे हैं और यह

पदोन्नति उनकी कड़ी मेहनत और विभाग के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। इस सम्मान से उत्साहित नवनियुक्त हेड कांस्टेबल राहुल चौहान ने उच्चाधिकारियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक ईमानदारी व तत्पर रहने का संकल्प लिया।

जिलाधिकारी ने कोषागार हापुड़ से पेंशन पा रहे सभी पेंशनरों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु दिए निर्देश

वेलकम इंडिया ब्यूरो

हापुड़। हापुड़ जनपद की कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कविता मीना की अध्यक्षता में पेंशन पा रहे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में आ रही समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सेवानिवृत्त शिक्षक, कर्मचारी एवं पेंशनर संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन, पारिवारिक पेंशन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अन्य



भत्तों से संबंधित समस्याओं के

समाधान को लेकर विचार विमर्श

किया गया। जिलाधिकारी ने कोषागार

हापुड़ से पेंशन पा रहे सभी पेंशनरों की पेंशन से संबंधित समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत समय से तथा एक माह के भीतर सभी प्रकार का भुगतान कराना सुनिश्चित करें। सरकारी सेवा से रिटायर होने के उपरांत पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों का पेंशन में सहयोग किया जाए।

जिलाधिकारी ने संबंधित

अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जो कर्मचारी सरकारी सेवा से रिटायर हो गए हैं और उनकी अभी तक पेंशन लागू नहीं हुई है उनका 15 दिवस के अंदर समाधान करना सुनिश्चित करें।

साथी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने कर्मचारियों का आगामी माह मार्च 2027 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की सूचित तैयार कर ले जिससे समय पर उनके रिटायरमेंट की कार्रवाई समय से की जा सके।

नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने मिलकर किया पौधारोपण



बिजनौर (वेलकम इंडिया)। नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने मिलकर वैष्णो विहार कॉलोनी में अमरुद, आम, पीपल, कचनार, बकैन, बड़, जामुन आदि के फलदार एवं छायादार पौधे लगाकर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं प्रकृति संवर्धन का संदेश देने का कार्य किया। इस मौके पर संगठन की अध्यक्ष पद्म गुप्ता, शिक्षा गुप्ता, पूनम शर्मा, संतोष, रिंकी मसीह मंत्री मनीषा गुप्ता, करुणा अग्रवाल, रश्मि तोमर, शीतल भारद्वाज, सुनीता शर्मा सदस्य मीना शर्मा आदि बहनें मौजूद रही।

को नियंत्रित करते हैं मिट्टी के कटाव को रोक कर बाढ़ जैसी आपदाओं को नियंत्रित कर हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर प्राकृतिक संरक्षण एवं हरित भारत के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। इस मौके पर संगठन की महामंत्री शास्वती चौधरी, उपाध्यक्ष निधि वर्मा, वंदना गुप्ता, शिक्षा गुप्ता, पूनम शर्मा, संतोष, रिंकी मसीह मंत्री मनीषा गुप्ता, करुणा अग्रवाल, रश्मि तोमर, शीतल भारद्वाज, सुनीता शर्मा सदस्य मीना शर्मा आदि बहनें मौजूद रही।

225 ग्राम चरस के साथ शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार

वेलकम इंडिया संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक के कुशल निर्देशन में नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए तीनों जनपदों में विशेष अभियान ऑपरेशन सवेरा- नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के मार्गदर्शन, एसपी सिटी और क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुतुबशेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर



कार्रवाई करते हुए एक शातिर नशा तस्कर को अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना कुतुबशेर के प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के

नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आज 13 जुलाई 2026 को मानकमऊ खंडहरों से करीब 50 मीटर नहर की तरफ घेराबंदी कर शातिर अभियुक्त अरशद उर्फ कनकटा पुत्र भूरा उर्फ

पाल्ली उर्फ फैजान (निवासी मोहल्ला इनाम कॉलोनी, हाल निवासी मोहल्ला नसीर कॉलोनी, थाना कुतुबशेर, सहारनपुर) को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से 225 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना कुतुबशेर में आरोपी के खिलाफ मामला पंजीकृत किया गया है। पुलिस आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। पकड़ा गया आरोपी अरशद उर्फ कनकटा कुख्यात अपराधी है और उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ थाना

कुतुबशेर और थाना कोतवाली मंडी में गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट (आयुध अधिनियम), जानलेवा हमला (धारा 307 भादवि), गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन अपराधों के तहत कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं।

वह लगातार क्षेत्र में अवैध गतिविधियों में लिप्त रहा है। इस नशा तस्कर को दबोचने में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी, उपनिरीक्षक अजयपाल सिंह, उपनिरीक्षक आकाश कुमार, हेड कॉन्स्टेबल रूपेन्द्र सिंह और रिफ़ूट कॉन्स्टेबल सुमित कुमार की मुख्य भूमिका रही। एसपी सिटी ने पुलिस टीम की इस त्वरित कामयाबी को सराहना की है।

नाबालिग की हत्या कर शव नहर में फेंकने वाला आरोपी आयान गिरफ्तार

वेलकम इंडिया संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर जनपद की थाना बडगाँव पुलिस ने नाबालिग युवती का अपहरण कर उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंकने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। थाने में तहरीर देकर वादी की नाबालिग लडकी के घर से बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर मुकदमा पंजीकृत कराया था।

गुमशुद का शव बेलडा नहर से बरामद किया गया। जिसके बाद वादी अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक देवदं के कुशल नेतृत्व में



देने के सम्बन्ध में दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण तथा क्षेत्राधिकारी देवबंद द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा पुलिस टीम का गठन कर घटना का सफल अनावरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक देवदं के कुशल नेतृत्व में

गठित पुलिस टीम ने आज मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त आयान पुत्र साबिर उर्फ शम्भू निवासी ग्राम बेलडा बुजुर्ग थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों का एडीएम ने लिया जायजा



वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। बरसात के मौसम में संभावित बाढ़ से सुरक्षा एवं बचाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सत्य प्रकाश ने सोमवार को मेहदावल तहसील क्षेत्र में राप्ती नदी के दाहिने तट पर स्थित करमैनी-बेलौली तटबंध का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्रेनेज खंड-2 के अधीन संचालित नई बाढ़ परियोजनाओं तथा बाढ़ पूर्व तैयारियों का जायजा लिया। एडीएम ने नवगों, बड़या ठाठर और बेलौली स्थित बाढ़ चौकियों के स्तरों का निरीक्षण किया, जहां सीमेंट की खाली बोरियां, नालॉन क्रेट, ब्रिक

रोड़ा तथा गिट्टी-मोरंग सहित अन्य आवश्यक फिल्टर सामग्री पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पाई गई। उन्होंने अधिशासी अभियंता अजय कुमार, सहायक अभियंता मनीष राय और अन्य अभियंताओं से तटबंध पर चल रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को तटबंधों की निरंतर निगरानी रखने, संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी मेहदावल अरुण कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

तालुका विधिक सेवा समितियों के पदेन सचिवों के साथ आयोजित हुई बैठक

विधिक सेवा से संबंधित स्कीमों तथा ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्युनिटी मीडियेटर चिन्हित करने के बावत हुई चर्चा

वेलकम इंडिया संवाददाता

संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश रणधीर सिंह के निर्देशन में आज दिनांक 13 जुलाई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना था।

बैठक के दौरान सचिव महोदय



ने तालुका स्तर पर विधिक सहायता एवं जागरूकता कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने, पात्र व जरूरतमंद लोगों तक निःशुल्क विधिक सेवाएँ पहुँचाने, प्री-लिटिगेशन मामलों के अधिकतम निस्तारण, लोक अदालतों की सफलता सुनिश्चित करने तथा विभिन्न

विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर विधिक साक्षरता कार्यक्रमों को गति देने के निर्देश दिये।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्युनिटी मीडियेटर चिन्हित करने तथा आगामी विशेष अभियानों, विधिक जागरूकता शिविरों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में

स्कूटी चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी की एक्टिवा बरामद

वेलकम इंडिया संवाददाता

सहारनपुर। जनपद की थाना कुतुबशेर पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने वांछित चल रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की गई होंडा एक्टिवा स्कूटी बरामद कर ली है। पुलिस आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 30 जून 2026 को पीड़ित कोशर अली पुत्र मौ0 इलियास (निवासी मोहल्ला आनंद नगर, थाना कुतुबशेर, सहारनपुर) ने थाने में एक लिखित तत्वावस्कूटी चोरी कर ली है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर थाना कुतुबशेर पुलिस ने तत्काल अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच



शुरू कर दी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए जनपदभर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में कुतुबशेर पुलिस ने आज 13

जुलाई 2026 को इस चोरी की घटना का सफल अनावरण कर दिया। पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए वांछित शातिर चोर असद खान पुत्र राशद खान (निवासी मोहल्ला पठानपुरा, अफगानान मस्जिद वाली गली, थाना सदर बाजार, सहारनपुर) को दबनी कब्रिस्तान के बराबर से जा रहे खड़्गे पर तालाब के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

समेकित शिक्षा को धरातल पर उतार रहे करुणापति, कार्यों की चौतरफा सराहना

वेलकम इंडिया संवाददाता

सिद्धार्थनगर। जनपद में विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने और समेकित शिक्षा के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने के लिए जिला समन्वयक समेकित शिक्षा करुणापति के प्रयासों की चौतरफा सराहना हो रही है। विभागीय स्तर और स्थानीय प्रबुद्ध वर्ग द्वारा उनके कार्य व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठा को जिले के लिए एक मिसाल बताया जा रहा है। स्थानीय शिक्षकों और शिक्षाविदों का कहना है कि जिला समन्वयक के कुशल निर्देशन में समेकित शिक्षा के तहत संचालित योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद बच्चों तक पहुँच रहा है। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरणों का सुचारु वितरण और उनके अनुकूल शिक्षण माहौल तैयार करने में उन्होंने व्यक्तिगत रूचि दिखाई है। उनके इन संवेदनशील प्रयासों के कारण विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों के



नामांकन और ठहराव में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। जागरूक नागरिकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों के अनुसंधार, करुणापति न केवल प्रशासनिक कार्यों को चुस्ती से निपटाते हैं, बल्कि फील्ड में जाकर जमीनी हकीकत का जायजा भी लेते हैं। उनकी इस कार्यशैली से रिसोर्स शिक्षकों और विभागीय कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। एक संवेदनशील अधिकारी के रूप में उनका यह योगदान समाज के सबसे वंचित वर्ग के बच्चों के भविष्य को संवारने में मील का पत्थर साबित हो रहा है और पूरे शिक्षा विभाग के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है।

विधायक उमर अली खान का विरोधियों पर पलटवार, आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश, करेगे मानहानि का मुकदमा

वेलकम इंडिया संवाददाता

सहारनपुर। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बेहट विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमर अली खान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह निराधार, बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उनकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए विधायक उमर अली खान ने कहा कि लगभग एक वर्ष पूर्व भी उनके खिलाफ इसी प्रकार के आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया था।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को शिकायती



पत्र देकर पूरे मामले से अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह न्यायालय की शरण लेंगे और उपलब्ध ऑडियो तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि किसी भी व्यक्ति को झूठे आरोप लगाकर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं है। ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी को आर्थिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास न कर सके। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष

चौधरी अब्दुल वाहिद ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि कुछ लोग पत्रकारिता की आड़ लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है और तथ्यहीन आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र सिंह, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान, पूर्व सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान, पूर्व मंत्री लियाकत अली सहित समाजवादी पार्टी के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कालानमक चावल ट्रेड के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 से 24 जुलाई तक



वेलकम इंडिया संवाददाता

सिद्धार्थनगर। एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कालानमक चावल ट्रेड में लाभार्थियों के चयन के लिए साक्षात्कार 21 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी उपायुक्त उद्योग अधिकारी शिवशंकर कुमार, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र ने दी है।

उपायुक्त उद्योग के अनुसार साक्षात्कार के लिए गठित समिति की बैठक प्रतिदिन अपराह्न 12 बजे जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र, सिद्धार्थनगर में होगी। योजना के तहत आवेदन करने वाले सभी पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि एवं समय पर आवश्यक अभिलेखों सहित उपस्थित होकर साक्षात्कार में भाग लेने की अपील की गई है, ताकि चयन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण की जा सके।

एसआरएम मोदीनगर कॉलेज में बी.फार्म के विद्यार्थियों हेतु आटवे इंडक्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली-एनसीआर परिसर स्थित एसआरएम मोदीनगर कॉलेज ऑफ फार्मेसी द्वारा नवप्रवेशित बी.फार्म (2026-27) के विद्यार्थियों का महादेव लाल श्रॉफ ऑडिटोरियम में आटवे इंडक्शन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संस्थान के शैक्षणिक वातावरण, व्यावसायिक नैतिकता, संस्थागत मूल्यों तथा फार्मेसी क्षेत्र में उपलब्ध भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण, दीप प्रज्वलन एवं



सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके पश्चात मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का सम्मान किया गया। स्वागत भाषण डॉ. मनीष पाल सिंह, प्राचार्य (प्रभारी), फार्मेसी विभाग द्वारा दिया गया, जिन्होंने सभी अतिथियों, संकाय

सदस्यों, नवप्रवेशित विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर डॉ. रोहित जोशी, प्रधान वैज्ञानिक, प्लांट टिशू कल्चर प्रयोगशाला, जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग,

सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी, पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक सोच, अनुसंधान की

भावना, नवाचार तथा व्यावसायिक नैतिकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री रमेश कुमार गुलेरिया, क्यूसी एवं साइट हेड, प्लिका वैक्सीन्स प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद ने औषधि उद्योग के वर्तमान परिदृश्य, गुणवत्ता नियंत्रण, उद्योग की अपेक्षाओं तथा रोजगार की संभावनाओं पर अपने अनुभव साझा किए और विद्यार्थियों को उद्योग के अनुरूप स्वयं को तैयार करने का संदेश दिया।

डॉ. मुदित दीक्षित, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ने हवैसिक करियर के लिए फार्मासिस्टों का निर्माण विषय पर मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन डॉ. सचिन सिरौही, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी, इन्क्यूबेशन सेंटर ने हस्टार्ट-अप इकोसिस्टम एवं नवाचार विषय पर प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। डॉ. पल्लवी जैन, छात्र कल्याण प्रमुख ने हवैसिक संघर्ष पर दूर एक दूसरा घर विषय पर विद्यार्थियों को संस्थान के छात्र-केंद्रित वातावरण से अवगत कराया।

महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में 15 जुलाई को अनुमोदित पुस्तकों की बिक्री हेतु पुस्तक मेले का आयोजन



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज, सारा रोड, गोविंदपुरी, मोदीनगर में दिनांक 15 जुलाई 2026 (बुधवार) को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित पुस्तकों की बिक्री हेतु पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ. अंशु सिंह ने बताया कि इस पुस्तक मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को गुणवत्तापूर्ण

पुस्तकें उचित एवं विभाग द्वारा अनुमोदित रियायती दरों पर उपलब्ध कराना है। मेले में कक्षा 9 से 12 तक की सभी विषयों की पुस्तक उपलब्ध होगी। उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं, अभिभावकों, से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में पुस्तक मेले में पहुंचकर विभाग द्वारा मान्य कम कीमतों पर उपलब्ध उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का लाभ उठाएं जिससे छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न ना हो।

लायंस क्लब मोदीनगर सेंट्रल ने शिक्षाविदों और मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। लायंस इंटरनेशनल मंडल 32131 के गवर्नर लायन आदित्य गुप्ता के 'एक दिन, एक एक्टिविटी' अभियान के अंतर्गत लायंस क्लब मोदीनगर सेंट्रल ने लायंस ओलंपियाड फाउंडेशन के तत्वावधान में सम्मान समारोह आयोजित किया। समारोह में दयावती मोदी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य डॉ. वी.के. राणा को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 'भारत शिक्षा रत्न सम्मान-2026' से सम्मानित किया गया। क्लब पदाधिकारियों ने कहा कि डॉ. राणा का शिक्षा के प्रति समर्पण समाज के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 10 के मेधावी विद्यार्थियों अभिराज राणा, कामिका सोम और प्रखर को भी उनकी शानदार शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए



सम्मानित किया गया। अतिथियों ने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत करने और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में लायंस क्लब मोदीनगर सेंट्रल के अध्यक्ष डॉ. जी.एस. सचदेवा, सचिव निशांत अग्रवाल, प्रोजेक्ट चेयरमैन

अंकुर सक्सेना सहित क्लब के अनेक सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। पुरुषार्थ कांतिकारी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कौशिक का अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर चौथे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा।



संगठन के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी के नाम नाथब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जिसमें अवैध अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर 20 जुलाई को सड़क जाम की चेतावनी दी गई है।

ज्ञापन में कहा गया है कि पुरुषार्थ कांतिकारी संगठन मोदीनगर सिखड़ा रोड पर सड़क अतिक्रमण हटवाने हेतु तहसील प्रांगण में 11.05.2026 से 09 दिन धरना दिया।

जिस पर उपजिलाधिकारी मोदीनगर व अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग गाजियाबाद

द्वारा एक माह के अंदर उपरोक्त अतिक्रमण हटवाने का आश्वासन देकर घरना स्थगित कराया लेकिन अभी तक उपरोक्त मार्ग अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया। पुनः आमरण अनशन 10.07.2026 से लगातार तहसील में चल रहा है। अगर जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण नहीं हटवाया तो विचार्य होकर संगठन 20.07.2026 को मोदीनगर तहसील के सामने रोड जाम कर तहसील प्रशासन का ध्यान आकर्षित करेगा।

दिल्ली मंडल के मोदीनगर रेलवे स्टेशन को पुनर्विकसित किया गया स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया है

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया है। मोदीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 25.75 करोड़ रुपये के बजट से किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य संपर्क और पहुंच में सुधार के इरादे से देश भर के रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है।



कुल मिलाकर, अमृत भारत स्टेशन योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो भारत में रेलवे प्रणाली का उपयोग करने वाले लाखों लोगों को लाभान्वित करेगी। इस योजना की परिकल्पना यात्रियों को सभी आधुनिक सुविधाओं

के साथ अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है। इससे यात्रियों का यात्रा अनुभव बेहतर होगा। इस परियोजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ना और यात्रियों को बेहतर पहुंच प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों का विकास करना है। इस योजना में संपर्क और पहुंच में

सुधार के लिए सड़कों, फुटपाथों और अन्य बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। इन स्टेशनों का पुनर्विकास दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ-साथ यात्रियों की निर्बाध आवाजाही प्रदान करने की दृष्टि से किया गया है।

स्टेशन भवन का नवीनीकरण

किया गया है। 12 मीटर चौड़ा फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाया गया है। एक नया पार्किंग क्षेत्र विकसित किया गया है। एक नया सकुलेंटिंग एरिया बनाया गया है। एक नया प्रतीक्षालय और शौचालय ब्लॉक बनाया गया है। प्लेटफॉर्म शेल्टर और प्लेटफॉर्म सतह में सुधार किया गया है। दिव्यांगजनों के लिए व्यापक सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिनमें एंटी रैप, टैक्टाइल पाथवे, सुगम्य शौचालय, वाटर व्यू, पार्किंग और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। दो लिफ्ट लगाई गई हैं जो यात्रियों, विशेषकर बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को लाभान्वित करेंगी। स्टेशन भवन पर फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। स्टेशन को सुंदर बनाने के लिए भूदृश्यकरण कार्य किया गया है।

मुल्तानीमल मोदी महाविद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन

अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। मुल्तानीमल मोदी महाविद्यालय, मोदीनगर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार के संपूर्ण प्रदेश में सामूहिक स्तर वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिससे प्राप्त करने हेतु प्रत्येक संस्थान में वृक्षारोपण किया जा रहा है। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. वंदना शर्मा ने महाविद्यालय के प्रांगण वृक्षारोपण कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम महाविद्यालय की 'पर्यावरण एवम् वृक्षारोपण समिति' के तत्वाधान में किया गया। समिति की समन्वयक प्रो. वसुधा शर्मा ने बताया कि वृक्षों के द्वारा पर्यावरण को पुनर्जीवन प्रदान करने का कार्य करता है यह हमारा नैतिक एवम् मानवीय



दायित्व है कि पर्यावरण को सशक्त बनाए रखें। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक एवम् समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. अमर सिंह कश्यप ने बताया कि कैम्पस में 160 पौधों का रोपण किया गया जिसमें 40 पौधे फलदार वृक्ष के, 20 औषधीय, 40 पौधे एस्थेटिक, अन्य प्रकार के 60 वृक्ष लगाए गए।

नोएडा में मचा हड़कंप ई-मेल से डीएम कार्यालय को उड़ाने की धमकी

बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और फायर टीम ने खंगाला परिसर, जांच में नहीं मिला कोई विस्फोटक



कपिल चौहान

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी (डीएम) कार्यालय को सीमावार की ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही थाना सूरजपुर पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों के साथ डीएम कार्यालय परिसर को घेर लिया और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पुलिस के अनुसार, 13 जुलाई 2026 को डीएम कार्यालय में ई-मेल के माध्यम से बम होने की सूचना



प्राप्त हुई। इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड (बीडीएस), एंटी-सबोटाज चेक टीम, डॉग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। सभी टीमों ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। प्रारंभिक जांच में किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री नहीं

मिली। पुलिस ने बताया कि वर्तमान में स्थिति पूरी तरह सामान्य है तथा डीएम कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गई है। पुलिस ई-मेल भेजने वाले की पहचान और उसके स्रोत का पता लगाने में जुटी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर माध्यम से भी जांच की जा रही है।

आरना का जन्म दिवस पर आशीर्वाद देकर दी शुभकामनाएं, भंडारे का आयोजन



अनिल वशिष्ठ

मोदीनगर(वेलकम इंडिया)। गांव सीकरी कलां की पूर्व प्रधान श्रीमती अंजू त्यागी की प्रपौत्री एवं श्रीमती मानसी त्यागी व अविनाश त्यागी की पुत्री आरना का दूसरा जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया।

इस मौके पर हॉंडा शोरूम के सामने भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे का शुभारंभ पूर्व विधायक प्रशांत चौधरी, विवेक भाटी एमडी वुडहिल, पतंजलि के प्रभारी स्वामी आरोग्य देव व प्रदीप कौशिक ने किया। जिसमें सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष विनोद वैशाली, पूर्व विधायक प्रतिनिधि पंकज गुर्जर, ब्लॉक प्रमुख राहुल डैनी, गन्ना समिति के अध्यक्ष राजन चौधरी, प्रदीप त्यागी, गीत कौशिक, पंकि की चौधरी, विवेक भाटी, कुणाल त्यागी, डा बबली गुर्जर पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व विधायक सुदेश शर्मा, प्रशांत त्यागी, प्रीतम सेनी सभासद, राहुल, जयप्रकाश वशिष्ठ, शैलेंद्र प्रधान, देवव्रत धामा, मनीषा त्यागी, अनिल गौतम जिला पंचायत सदस्य, दिनेश शर्मा, अनुज शर्मा, नितिन, अक्षय, विष्णु उपाध्याय, उत्तम चंदेला, ऋतिक गुर्जर आदि गणमान्य लोगों ने आरना को आशीर्वाद और अपनी शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में पधारे सभी गणमान्य लोगों का अविनाश त्यागी ने आभार व्यक्त किया।

एक्स-रे टेक्नीशियन का तबादला बना टीबी मरीजों की परेशानी, प्रतिदिन करीब 50 को एक्स-रे की जरूरत लेकिन सुविधा ठप

गाजियाबाद (वेलकम इंडिया)। जिला क्षय रोग (टीबी) अस्पताल में एक्स-रे टेक्नीशियन के तबादले के बाद मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में एक्स-रे सुविधा प्रभावित होने से टीबी मरीजों को जांच के लिए दूसरे अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इलाज के दौरान आवश्यक एक्स-रे जांच के लिए मरीजों को महर्षि मनोहर लाल (एमएमएल) अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां उन्हें दोबारा पचा बनवाने

और चिकित्सक से एक्स-रे लिखवाने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। इससे मरीजों का समय और पैसा दोनों खर्च हो रहे हैं, वहीं गंभीर मरीजों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। टीबी अस्पताल में प्रतिदिन करीब 200 से 250 मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। इनमें से औसतन 50 मरीजों को हर दिन एक्स-रे जांच के लिए मरीजों को महर्षि मनोहर लाल (एमएमएल) अस्पताल भेजा जा रहा है, जहां उन्हें दोबारा पचा बनवाने

स्थानांतरण के बाद यह सुविधा लगभग ठप हो गई है। ऐसे में मरीजों को मजबूरी में एमएमएल अस्पताल भेजा जा रहा है। मरीजों का कहना है कि टीबी अस्पताल से एमएमएल अस्पताल पहुंचने के बाद भी उनकी परेशानी खत्म नहीं होती। वहां सबसे पहले नया पंजीकरण करना पड़ता है, फिर डॉक्टर से परामर्श लेकर दोबारा एक्स-रे की पची बनानी पड़ती है। इसके बाद जांच के लिए लंबी कतार में इंतजार करना पड़ता है।

क्रिसेंट सोसाइटी में विधायक ने विकास कराने का दिया आश्वासन

वेलकम इंडिया संवाददाता

गाजियाबाद। प्रताप विहार के सेक्टर 11 स्थित क्रिसेंट सोसाइटी में रविवार रात को एक समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें शहर विधायक संजीव शर्मा ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरडब्ल्यू के अध्यक्ष श्यामसुंदर त्यागी ने की। इस मौके पर विधायक संजीव शर्मा ने कहा कि सोसाइटी का विकास कराना पहली प्राथमिकता है। इस दौरान उनसे सोसाइटी में हाई माक्स लाइट लगवाने



की मांग की। विधायक ने जल्द मांग पूरी करने को कहा। इस मौके पर सतराम यादव, मेहराज, पवन

नायक, रतन, विपिन उज्जवल, राकेश कुमार, नासिर अली, यशपाल, मनीष व मनक सहित अन्य लोग मौजूद थे।

